



तापमान 16 - 27
आर्द्रता 35%
सूर्योदय: 06:18 सूर्यास्त: 17:19



समाज्ञा



आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 विश्व कप से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल किया पृष्ठ 8

स्थानीय खबरें पृष्ठ तीन, चार और पांच पर

कोलकाता, माघ शुक्लपक्ष सप्तमी, वि.स. 2082, पृष्ठ 8, मूल्य 4.00 रुपये **सुविचार : सब कुछ नकल किया जा सकता है परन्तु ज्ञान और चरित्र असल रहते हैं।**



125 दिन की रोज़गार गारंटी



Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB - G RAM G
(विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025

अब गांव के लोग खुद बनाएंगे विकसित ग्राम पंचायत योजना



विकसित ग्राम पंचायत से विकसित भारत की ओर

कांग्रेस से कुछ 'मतभेद' हैं, इन्हें नेतृत्व के समक्ष उठाऊंगा: शशि थरूर (पृष्ठ 7)

भारत ने अंडर-19 विश्व कप मैच में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराया (पृष्ठ 8)

अब मिशन मोड में सरकारी नौकरी: प्रधानमंत्री मोदी

61 हज़ार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत देश के भीतर और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न देशों के साथ व्यापार और आवागमन संबंधी समझौते कर रहा है। मोदी ने यह बात 18वें रोजगार मेले में कही जहां उन्होंने विभिन्न सरकारी नौकरियों के 61,000 नियुक्ति पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सौंपे। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 45 स्थानों पर रोजगार मेलों को संबोधित करते हुए कहा, "भारत कई देशों के साथ व्यापार और आवागमन संबंधी समझौते कर रहा है। ये व्यापार समझौते देश के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं।" मोदी ने कहा कि दुनिया में युवाओं की सबसे अधिक संख्या भारत में है और उनकी सरकार देश के भीतर और



विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक बयान में कहा गया कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को साकार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। बयान में कहा गया कि इसकी शुरुआत के बाद से देश भर में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसमें बताया गया कि 18वां

रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया और भारत के सभी हिस्सों से चयनित नव-नियुक्त कर्मचारी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल हुए। नव-नियुक्त कर्म गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि में सेवाएं देंगे।

सरकारी नौकरी मिशन मोड में पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां मौजूद सभी युवाओं को बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, युवाओं को कोशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार के अवसर देना हमारी सरकार का लक्ष्य रहा है। सरकारी नौकरियों को मिशन मोड में लाने के प्रयास में, रोजगार मेला शुरू किया गया था। पिछले कुछ सालों में, रोजगार मेला एक संस्था बन गया है जिसके माध्यम से लाखों युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं।

बंगाल एसआईआर : निर्वाचन आयोग ने तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल लोगों के नाम वेबसाइट पर अपलोड किए

कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने शनिवार देर शाम को एसआईआर संबंधी तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। आयोग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अब जिला निर्वाचन अधिकारी अदालत के निर्देशानुसार सूची डाउनलोड करेंगे तथा उसे पंचायत भवनों और ब्लाक कार्यालयों में प्रदर्शित करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने 19 जनवरी को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह बंगाल के ग्राम पंचायत भवनों, तालुका

जीमेल, फेसबुक समेत कई इंटरनेट फर्म के 14.9 करोड़ खातों की लॉगिन जानकारी लीक

नयी दिल्ली : जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी दिग्गज इंटरनेट कंपनियों के 14.9 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजरनेम और पासवर्ड) कथित तौर पर लीक हो गए हैं। 'एक्सप्रेसवीपीएन' द्वारा प्रकाशित और साइबर सुरक्षा शोधकर्ता जेरेमिया फाउलर की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक रूप से उजागर हुए इस डेटा में जीमेल के 4.8 करोड़, याहू के 40 लाख, फेसबुक के 1.7 करोड़, इंस्टाग्राम के 65 लाख और नेटफ्लिक्स के 34 लाख खाते शामिल हैं। इसके अलावा आउटलुक के भी 15 लाख खातों की जानकारी लीक होने की बात कही गई है। फाउलर ने रिपोर्ट में कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध यह डेटाबेस पासवर्ड से सुरक्षित या एन्क्रिप्टेड नहीं था। इसमें कुल 14.94 करोड़ विशिष्ट लॉगिन और पासवर्ड मौजूद थे, जिनका कुल आकार 96 जीबी है। नमूनों की जांच में हजारों ऐसी फाइलें मिलीं जिनमें ईमेल, यूजरनेम, पासवर्ड और संबंधित अकाउंट्स के लॉगिन यूआरएल लिंक शामिल थे।

खुशियों की असली मिठास

भुजिया

खट्टा मीठा

चटपटा

काजू बारफ़ी

गुलाब जामुन

रसगुल्ला

सोन पापड़ी

Haldiram Bhujiawala Limited
Regd. Office : P-420, Kazi Nazrul Islam Avenue, VIP Road, Kolkata - 700 052
Burrabazar : 9, Jagmohan Mullick Lane, Kolkata - 700 007

SMART GOLD EXCHANGE FESTIVAL

GET 2% HIGHER VALUE ON OLD GOLD EXCHANGE FOR NEW JEWELLERY

INDIAN GEM & JEWELLERY CREATION

9B, Wood Street: Ground Floor, Kolkata 700 016 M +91 98910 89018 South City Mall: Ground Floor, 375, Prince Anwar Shah Road, Kolkata 700 068 M +91 98910 89029 City Centre II, Rajarhat : Block-B, 2nd Floor, Shop No. 201, New Town, Kolkata 700 157 M +91 98910 89066 Howrah: JP's AC Market (Shri Vindyalal Building), 35, Dr. Abani Dutta Road (Near Howrah AC Market) M +91 98910 89027 Vardaan Market: 106 Vardaan Market, 1st Floor, 25A, Camac Street, Kolkata 700 016 M +91 98910 89003 Bagnan: Glorious Shopping Complex, Near CTC Bus Stand, Shop No. 4, 1st Floor, Bagnan, Howrah 711 303 M +91 98910 89024 Durgapur: Shop No. 205, Dreamplex Mall, 1st Floor, City Centre, Durgapur 713 216 M +91 98910 89017 Serampore: Agnisha - II, Ground Floor, 30, K M Shah Street, Serampore, Hooghly 712 201 M +91 98910 89014

Diamond Jewellery, Solitaires, Hallmarked Gold Jewellery, Polki, Kundan-Jadua, Silver and Certified Gemstones with buy-back facility.

Authorised Retailer: Platinum & MMTC Gold & Silver Bars Toll Free No. 1800 889 1704

न्यूयॉर्क : अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क को हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली द्वारा माँस्को से की जाने वाली ऐसी खरीदारी बहुत अधिक घट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद के लिए 25 प्रतिशत शुल्क शामिल है। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। बेसेंट ने शुक्रवार को भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को एक "सफलता" बताया। उन्होंने 'पॉलिटिको' के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "हमने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था। इसके बाद उनकी रिफाइनिंगों द्वारा रूसी तेल की खरीद बहुत अधिक घट गई। इसलिए यह एक सफलता है। शुल्क अभी भी लागू हैं।"

हिंदू धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम नहीं, बल्कि एक साथ रहने का तरीका है : भागवत

रांची : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को यहां आदिवासी समूहों के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत के दौरान 'विविधता में एकता' के महत्व पर जोर दिया। उनसे बातचीत करते हुए भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम नहीं, बल्कि एक साथ रहने का एक तरीका है। आरएसएस के एक बयान में भागवत के हवाले से कहा गया है, "भारत की पहचान विविधता में एकता पर आधारित है। पूजा पद्धति के तरीके भले ही भिन्न हों, लेकिन सभ्यता के मूल मूल्य एक समान रहते हैं। दशकों के अनुभव और चिंतन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि समाज को सामूहिक रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि तमाम विविधताओं के बावजूद हम मूलतः एक हैं।" उन्होंने कहा कि 'हिंदू' शब्द बाद में सामने आया, लेकिन इसका सार 'जल, जंगल और खेती' में निहित है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि वेद और उपनिषद दर्शन की उत्पत्ति प्रकृति के साथ इसी संबंध से हुई है, और अथर्ववेद विविधता के प्रति सम्मान के विचारों को प्रतिबिंबित करता है, जहां धरती माता सभी चीजों का पोषण करती है और सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है।

SARDAR JODH SINGH

FOUNDER CHAIRPERSON, JIS GROUP
(1st February, 1920 - 25th January, 2018)

SARDARNI SATNAM KAUR

FORMER CHAIRPERSON, JIS GROUP
(15th April, 1929 - 11th January, 2022)

You are cordially invited to the annual memorial gathering in honor of our beloved Babuji Sardar Jodh Singh and Mataji Sardarni Satnam Kaur.

Bhai Saheb Bhai Jaskaran Singh ji Patiala Wale, Hazuri Ragi Sri Darbaar Sahib Amritsar & Bhai Saheb Bhai Baljeet Singh Ji U S A Wale, followed by Guru Ka Langar at Dunlop Gurudwara on 25th January, 2026 from 11AM onwards.

The JIS Family

एसआईआर के खिलाफ आज राज्यभर में तृणमूल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

तृणमूल सांसद, विधायकों चुनाव ‘वार रूम’ को तुरंत सक्रिय करें : अभिषेक बनर्जी

□ तृणमूल नेता ने प्रत्येक बुध में एक ‘बुध रक्षा समिति’ के तत्काल गठन का किया आह्वान

कोलकाता, समाज्ञा : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को पार्टी के सांसदों और विधायकों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव ‘वार रूम’ को तुरंत सक्रिय करें और 27 जनवरी से पार्टी नेतृत्व को नियमित रूप से अद्यतन जानकारी भेजते रहें। इस दिन, पार्टी नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए, अभिषेक बनर्जी ने भाजपा द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और ‘तार्किक विसंगतियों’ के माध्यम से



पात्र मतदाताओं को हटाने के कथित प्रयासों को विफल करने के लिए प्रत्येक बुध में एक ‘बुध रक्षा समिति’ के तत्काल गठन का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को ‘तार्किक विसंगतियों’

के माध्यम से मताधिकार से वंचित करने के प्रयासों के विरोध में तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा। तृणमूल नेता ने कहा कि इसके अलावा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज एसआईआर के खिलाफ प्रखंड और शहर स्तर पर धिक्कार/प्रतिवाद सभा आयोजित की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने दावा किया कि सूक्ष्म पर्यवेक्षकों द्वारा जिला चुनाव अधिकारियों से उनके ‘लॉगिंग’ संबंधी जानकारी मांगे जा रहे हैं और कहा कि पार्टी इस मुद्दे को कानूनी रूप से उठाएगी। अभिषेक बनर्जी ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पहले दिए गए

निर्देशों के बावजूद पार्टी में कई ‘वॉर रूम’ अभी तक सक्रिय नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि कई सांसद और विधायक इस लड़ाई में सक्रिय नहीं हैं और यह सिलसिला जारी नहीं रह सकता। जो लोग पार्टी के पक्ष में सक्रिय रूप से खड़े नहीं होंगे, उन्हें पार्टी का समर्थन नहीं मिलेगा। हमें पार्टी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा सत्र में भाग लेने के अलावा, प्रतिनिधियों को भाजपा के एजेंडे का मुकाबला करने के लिए भी समय देना चाहिए। तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने अभिषेक के हवाले से कहा कि एसआईआर के समाप्त होने में केवल 22 दिन शेष हैं। हमें और अधिक

सक्रिय होना चाहिए। इतने सारे ‘वॉर रूम’ अभी भी निष्क्रिय क्यों हैं? यदि आवश्यक हो, तो जन प्रतिनिधियों को ‘वॉर रूम’ को सुचारु रूप से चलाने के लिए अपनी जेब से खर्च करना चाहिए। अभिषेक ने कहा कि विधायक/सांसद द्वारा तैयार की गई ‘वॉर रूम’ रिपोर्ट 27 जनवरी से 15 फरवरी के बीच पार्टी के शीर्ष नेताओं को भेजी जानी चाहिए।

□ **महिला विंग और सरकारी योजनाओं का प्रचार**

अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की महिला शाखा को भी खास जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने ‘पड़ार संचलन’ अभियान के तहत हर वार्ड में 58 मिनट की डॉक्यूमेंट्री ‘लोकधी

एलो घोंरे’ दिखाने का निर्देश दिया। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए राज्य सरकार की योजनाओं और कामकाज को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है।

□ **भाजपा पर साधा निशाना**

अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने महाराष्ट्र और बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाकर चुनाव जीते थे और अब वही तरीका बंगाल में अपनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर खत्म होने में सिर्फ 22 दिन बचे हैं, ऐसे में सभी नेताओं को पूरी ताकत से मैदान में उतरना होगा और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देना है।

□ **चुनाव आयोग पर साधा निशाना**

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत ‘लॉजिकल डिस्क्रेमसी’ सूची में शामिल लोगों के नाम जारी करने में देरी को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और चुनाव आयोग की अपनी समयसीमा के बावजूद 24 जनवरी तक ग्राम पंचायतों और नगर वाडों में सूची सार्वजनिक नहीं की गई। तृणमूल नेता ने सवाल उठाया कि जिस सफ्टवेयर ने 16 दिसंबर को डाफ्ट रोल जारी होने के एक घंटे के भीतर कथित गड़बड़ियां पकड़ लीं, वही अब नाम उगार कर देने में असफल क्यों है। उन्होंने पूछा कि क्या देरी जानबूझकर की जा रही है?

सीमा पर कंटीले तार की बाड़ को लेकर हाईकोर्ट सरख्त, केंद्र और राज्य से हलफनामा तलब

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में कंटीले तार की बाड़ न होने से तस्करी बढ़ने के आरोपों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से हलफनामा तलब किया है। इस संबंध में दायर जहनित याचिका के आधार पर मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश दिया।

सीमावर्ती क्षेत्रों में कंटीले तार की बाड़ से जुड़े मुद्दे पर लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) सुब्रत साहा द्वारा हाईकोर्ट में जहनित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में दावा किया गया कि कई इलाकों में बाड़ नहीं होने के कारण तस्करी और अपराध की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार वर्ष 2016 से 2025 के बीच लगभग 2216.70 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में कंटीले

तार की बाड़ नहीं होने से अवैध तस्करी और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। इस मामले में केंद्र सरकार ने अदालत में राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। केंद्र का कहना है कि अब तक राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है, जिसके कारण कंटीले तार की बाड़ लगाने का काम संभव नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में केंद्र की ओर से हाईकोर्ट में आवश्यक जानकारी भी जमा कराई गई है।

अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों को देखकर डिवीजन बेंच ने भी चिंता व्यक्त की। हाईकोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार की स्थिति और स्पष्ट रख जानने के लिए दोनों पक्षों से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हलफनामे दाखिल होने के बाद ही अदालत इस मामले में आगे का निर्णय लेगी।

एसआईआर : प्रक्रिया में उत्पीड़न का आरोप, बर्दवान स्टेशन पर स्थानीय लोगों का रेल अवरोध

बर्दवान : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में कथित उत्पीड़न के विरोध में शनिवार को बर्दवान रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों पर उत्तकर अवरोध किया, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार सुबह करीब 11.30 बजे स्थानीय निवासी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर स्टेशन परिसर में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। देखते ही देखते स्थिति उग्र हो गई। प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने रेलवे ट्रैक पर लेटकर रेल अवरोध किया, जिसके कारण कई लोकल ट्रेनें रास्ते में ही रुक गईं। कुछ ट्रेनें आधे घंटे से अधिक समय तक फंसी रहीं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर उन्हें बार-बार बुलाकर परेशान किया जा रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम



स्थानीय निवासी हैं। बांग्लादेशी पहचान के नाम पर हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? बार-बार एक ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेल अवरोध के चलते स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

एक यात्री ने एसआईआर प्रक्रिया में उत्पीड़न के आरोप का समर्थन तो किया, लेकिन रेल अवरोध को उचित नहीं बताया। बाद में मौके पर पहुंची भारी संख्या में पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार फिलहाल रेल सेवा सामान्य हो चुकी है।

एसआईआर : बंगाल में सुनवाई की निगरानी के लिए 294 वरिष्ठ माइक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त

कोलकाता, समाज्ञा : निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने राज्य में मतदाताओं की मसौदा सूची पर दावों और आपत्तियों पर चल रही सुनवाई की समीक्षा के लिए 294 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक-एक वरिष्ठ माइक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इन 294 वरिष्ठ सूक्ष्म-पर्यवेक्षकों को आयोग द्वारा सुनवाई सत्र की समीक्षा के लिए पहले से नियुक्त 6,600 माइक्रो-ऑब्जर्वर से ऊपर रखा गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, माइक्रो-ऑब्जर्वर और वरिष्ठ माइक्रो-ऑब्जर्वर के पदक्रम और

कार्यभार में कुछ अंतर हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने हाल ही में ओडिशा, बिहार और झारखंड के अपने समकक्षों को वरिष्ठ माइक्रो-ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्तियों के लिए अधिकारियों को भेजने के लिए पत्र भेजे थे। इन तीनों राज्यों से वरिष्ठ माइक्रो-ऑब्जर्वर का चयन कर लिया गया है और वे 26 जनवरी को राज्य में अपने-अपने कार्यभार संभालेंगे। वे सुनवाई सत्र के पूरा होने तक पश्चिम बंगाल में रहेंगे, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

बंगाल ने राजस्व व्यय की वृद्धि पर लगाया अंकुश, पूंजीगत खर्च में आई गिरावट : रिपोर्ट

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले आठ महीनों में अपने राजस्व व्यय की वृद्धि को नियंत्रित रखने में सफल रही है। ‘केयएज रेटिंग्स’ की राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जहां कई राज्य खर्च के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं, वहीं अप्रैल-नवंबर की अवधि में पश्चिम बंगाल का राजस्व व्यय सालाना आधार पर केवल 3.8 प्रतिशत बढ़ा। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में दर्ज की गई 16.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले काफी कम है। एजेंसी के विश्लेषण के मुताबिक, आलोच्य 22 राज्यों के कुल राजस्व व्यय में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत रही, जो राज्य के संतुलित खर्च को दर्शाती है। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल को उन राज्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है जिनकी राजकोषीय स्थिति चिंताजनक है। इसके विपरीत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने इस अवधि के दौरान अपने बजटीय राजकोषीय घाटे का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च कर दिया है। हालांकि, रिपोर्ट में पूंजीगत व्यय के मोर्चे पर कमजोरी की ओर भी संकेत किया गया है। अप्रैल-नवंबर के दौरान पश्चिम बंगाल के पूंजीगत खर्च में सालाना आधार पर 35.1 प्रतिशत की गिरावट आई। पिछले साल इसी अवधि में यह गिरावट 13.0 प्रतिशत थी। विश्लेषण किए गए 22 राज्यों के कुल पूंजीगत व्यय में पश्चिम बंगाल की हिस्सेद-री मात्र 2.1 प्रतिशत रही, जो इसे समग्र राज्य पूंजीगत व्यय में कम योगदान देने वाले राज्यों की सूची में रखता है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना
ई-निविदा सूचना क्रमांक: 04-सीईई- सी-एसईसीआर-2026, दिनांक-21/01/2026
कार्य का नाम : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर और नामपुर मंडल में निम्नलिखित इलेक्ट्रिकल वृट्टिनिर्देश की कार्यवाही/कन्वर्जन/मॉडिफिकेशन/अडरग्राउंडिंग के लिए इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन का काम: (i) जलकम्हार-हंगराह के बीच 33 केवी. डी.सी. -01 नग: (ii) वसरातकान राजनारायन के बीच 33 केवी. एस.सी. 01 नग: (iii) रसमडा-मुहरीपार के बीच 33 केवी. डी.सी. -01 नग: (iv) लाटबोर-बालोदे के बीच 11 केवी. एच.टी. 07 नग. एच.टी. लाइन-05 नग और ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग-05 नग: (v) राजनारायन इस्ट एच.टी. गेट के पास 04 पोल इन्वर्टर (11 KV) 01 नग: (vi) कैप ऑफिस इन्वू, आर. एस., रायपुर में 11 केवी. 02 नग, (vii) डुर्ग वाई में ताट्टा का टैरिड टावर-डिस्टेंसिंग 01 नग और (viii) डी. एच. बी. एस. में ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग-01 नग और 33 केवी. पावर लाइन क्रॉसिंग-01 नग
निविदा सूचना : रु. 2,98,52,943.83 (रुपये दो करोड़ अठ्ठावन लाख बावन हजार नौ बी तैरातिस दमयन्त आठ तीन पाय) **स्थाना राशि :** 2,99,300/- (रुपये दो लाख नित्यायसे हजार तीन सौ पाय) **निविदा बंद होने का समय एवं दिनांक :** 16-02-2026 को 15:30 बजे। **निविदा खुलने का समय एवं दिनांक :** 16-02-2026 को 15:45 बजे। **कार्य पूर्णता की अवधि:** 08 (आठ माह) एल. ओ. ए. जारी होने के तारीख के बाद से। **वेबसाइट का विवरण तथा नोटिफ बाई का स्थान :** उपर दिए गए कार्य के लिए विस्तृत जानकारी/ई-निविदा दस्तावेज प्राप्त का मागदंड तथा अन्य विस्तृत विवरण हेतु ई-निविदा कागजात, जो हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है उसे डाउनलोड कर / देख सकते हैं।
सहा. कार्य. विद्युत अभियंता (निर्माण)
सीपीआर / 10/AM/643 **ड.ए.म. रेलवे, रायपुर**
f South East Central Railway X @cecrail

पश्चिम मध्य रेल

विद्युत निगम (कर्मण-विद्युत शाखा)
ई-निविदा सूचना
एन.आई.टी. नं. जबल-टीआरडी- निविदा-2025-07 दिनांक 22/01/2026
वरिष्ठ निगम विद्युत इंजीनियर/कर्मण-निर्माण/परिचय मध्य रेल, जबलपुर भारत संच के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी और से निम्नलिखित कार्य करने के लिए अनुमोदी ठेकेदारी से मुख्य निविदाएं आमंत्रित करते हैं। ठेकेदारी के पास राज्य सरकार द्वारा जारी सिविलीय लायसेंस (कर्म के नाम से या कर्म के किसी पार्टनर के नाम से या स्वयं के नाम से) यदि सोल प्रोपराइटर हो। आई ई. नियम 1956 के अनुसार होना चाहिए। कार्य का नाम - जबलपुर डिवीजन में टीएसएस/एसपी/एसएसपी आदीयु में आरडीएसओ विनिर्देश क्रमांक टीआईई/एसपीसी आरसीसी/एससीएडीए/0134 के अनुसार रकबाड निगम में साइबर सुखा का कार्यवाहन एवं फनीयर अपग्रेडेशन। कार्य स्थल- जबलपुर मण्डल। कार्य की अवधि- 12 माह, कार्य की कीमत (टेंडर वेर्यु)- रुपये 4,10,69,096.07/- (रुपये चार करोड़ चार लाख चत्तरह हजार छियासठ एवं सात पैसे मात्र)। **बनाना राशि** - रुपये 3,55,400.00/-, निविदा जमा करने/खुलने की अंतिम तिथि एवं समय- 20/02/2026 1500 बजे। 20/02/2026 1530 बजे, निविदा सूचना की पूर्ण जानकारी रेलवे वेबसाइट- <https://www.ireps.gov.in> निविदाकर्ता अपनी निविदाएं आई आई एच एल के माध्यम से <https://www.ireps.gov.in> पर ऑन लाईन निविदा करें। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे समय समय पर बदलाव व शुद्धि पत्रों हेतु IREPS की वेबसाइट www.ireps.gov.in देखते रहें न्यूनतम पात्रता मान दण्ड टेण्डर फार्म के अनुसार और ज्वाइंट केन्चर व साइडोरी इस निविदा के लिए लागू होंगी। (हस्ता)
कुते वरि मं.वि. इंजी. क.वि. पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर
सच माता अभियान एक कदम सचता की ओर

माध्यमिक के एनरोलमेंट-एडमिट को लेकर बड़ी राहत, दुबारा खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल



कोलकाता : विद्यालय स्तर की वृट्टियों के कारण जिन परीक्षार्थियों को माध्यमिक परीक्षा का एनरोलमेंट और एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया था, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रातय बसु ने इस संबंध में अहम जानकारी दी है। उन्होंने अपने एकस (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट कर बताया कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा

बोर्ड की ओर से ऑनलाइन एनरोलमेंट पोर्टल एक बार फिर खोला जा रहा है। बोर्ड सूत्रों के अनुसार, यह ऑनलाइन एनरोलमेंट पोर्टल 27 जनवरी दोपहर 12 बजे से 28 जनवरी दोपहर 12 बजे तक खुला रहेगा। इस निर्धारित समय के भीतर रचित परीक्षार्थी दोबारा आवेदन कर अपना एनरोलमेंट पूरा कर सकेंगे और एडमिट कार्ड प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने अपने पोस्ट में स्पष्ट किया कि यह विशेष अवसर पूरी तरह से परीक्षार्थियों के हित में दिया जा रहा है, ताकि विद्यालयों की लापरवाही का खामियाजा छात्रों को न भुगतना पड़े। इस घोषणा के बाद माध्यमिक परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के बीच काफी राहत देखी जा रही है।



कोलकाता, समाज्ञा

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीति हलचल बढ़ रही है। भाजपा और टीएमसी दोनों तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। इस बीच, शनिवार को भाजपा ने राज्य संकल्प पत्र समिति का गठन किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक



भट्टाचार्य की मंजूरी के बाद यह तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। इस कमिटी का उद्देश्य राज्य के मुख्य मुद्दों की पहचान करके आम जनता, विशेषज्ञों और समाज से संगठनों और कार्यकर्ताओं से सुझाव लेना है। इसके आधार पर पार्टी घो-षणा पत्र का मसौदा तैयार करेगी। संकल्प पत्र समिति का अध्यक्ष तपस



रॉय को बनाया गया है। जबकि, डॉ अशोक लहरी को संयोजक बनाया गया है। सह-संयोजक अग्रिमित्र पांडे होंगी। अन्य सदस्यों में डॉ चितरंजन मंडल, सांसद मनोज तिगा, डॉ स्वप्नदेश गुप्ता, शिशिर बाजोरिया, डॉ अमल कान्ति राय, वैशाली डालमिया, अनिर्बन गांगुली और देबजीत सरकार शामिल हैं।

ममता सरकार ने डीजी पद के लिए 8 लोगों की सूची भेजी

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य पुलिस के कार्यवाहक महानिदेशक (डीजी) राजीव कुमार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वे पिछले दो साल से उस पद पर हैं। इस बीच, अगले डीजी को लेकर उलझने में। राज्य सरकार ने सूची भेजने में इतनी देर कर दी है कि थूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है। अब, नवाज ने उस पद के लिए 8 नामों की सूची भेजी है। इन 8 लोगों के नाम 21 जनवरी को भेजे गए थे। और राजीव कुमार खुद उस सूची में हैं। अभी तक उन्हें कोई एक्सप्रेशन नहीं मिला है, यानी उनका अवधि नहीं बढ़ाया गया है। इसके बावजूद, उनका नाम सूची में रखा गया है। नतीजतन, प्रशासनिक गलियारों के एक हिस्से को लगता है कि शायद थूपीएससी इस सूची को भी स्वीकार न करें।

कोलकाता, समाज्ञा : राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक्स पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए बंगाल और पूरे देश की बेटियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि बेटियां समाज के भविष्य की शिल्पकार हैं और बंगाल में बालिकाओं का सम्मान और सशक्तिकरण केवल एक दिन नहीं, बल्कि पूरे वर्ष किया जाता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उनकी सरकार जन्म से लेकर शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा तक, जीवन के हर मोड़ पर बेटियों



के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि यह सफर ‘कन्याश्री’ योजना से शुरू होता है, जिसे लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने तथा बाल विवाह को रोकने के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने दावा किया कि इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ से अधिक लड़कियों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। ममता ने ‘सबूज साथी’ योजना का

भी उल्लेख किया, जिसके तहत छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए साइकिल दी जाती है। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में ‘शिक्षाश्री’, ‘ऐक्यश्री’, ‘मेधाश्री’, ‘तरुणेर स्वप्न’ जैसी योजनाओं के साथ मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते और मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाएं भी सरकार की ओर से प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह के समय लड़कियों को ‘रूपश्री’ योजना के तहत एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, वयस्क महिलाओं को ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के तहत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया

गया है, जिससे राज्य की 2.21 करोड़ महिलाएं हर महीने सीधे सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं। इसके साथ ही ‘स्वास्थ्य साथी’ कार्ड के माध्यम से महिलाओं और उनके परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया जा रहा है। अपने संदेश के अंत में ममता ने कहा कि आज बंगाल की बेटियां विज्ञान की प्रयो-गशालाओं से लेकर अंतरराष्ट्रीय खेल मंचों तक हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने बेटियों के लिए भयमुक्त, स्वतंत्र और सशक्त वातावरण उपलब्ध कराने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

www.samagya.in

समाज्ञा

NEWS PAPER ADVERTISING SOLUTION

MATRIMONIAL

EDUCATION

PROPERTY

RECRUITMENT

OBITUARY

NAME CHANGE

PUBLIC NOTICE

DISPLAY

TO AD IN SAMAGYA PLEASE CONTACT

samagyaadvt@gmail.com | samagya.in

81, Chintamani Dey Road, Howrah 711 101, Mobile: 70444 44522

गो-संरक्षण का दायित्व संभाले। गाय को मां की संज्ञा दी गई है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जेसे मां कहा जाता है, जिसमें सभी देवी-देवता आते हैं, का वास है, जो विश्व-वंदनीय है, आज उसी का अस्तित्व संकट में है। धड़ले से गो-वध जारी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को गायों के बड़ो प्रेम था और इसलिए उनका एक नाम गोपाल भी था। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सुरेश कुमार भुवालाल ने बताया कि कथा के ७०० दिन 25 जनवरी (रविवार) को कथा प्रसंग के अनुसार रुक्मिणी विवाह उत्सव श्री शशिकांत-बबीता पीठूरा तयजमानत्व में मनाया जायेगा और इस अवसर पर राज्य के माननीय मंत्री अरूप राय, उत्तर हावड़ा के विधायक गोमत चौधरी, समाजसेवी महेंद्र अग्रवाल अथवा अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहेगी।

न्यूज़ इन ब्रीफ

डीआरआई ने मांस का कीमा बनाने वाली मशीन में छिपाकर रखा 2.89 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया

मुंबई : राजस्व खुफिया निद-शालय (डीआरआई) ने यहां अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल पर सज्जी अरब से भेजी गई एक खेप में मांस का कीमा बनाने वाली मशीन में छिपाकर रखा गया 2.89 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने शनिवार को दी। अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई की मुंबई जोनल टीम ने एक खेप की जांच शुरू की, जिसमें मांस का कीमा बनाने वाली मशीन होने की घोषणा की गयी थी और मशीन को खोलने पर सोने के 32 टुकड़े बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि सीमा शुल्क अभिनियम के तहत कुल 1.815 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत 2.89 करोड़ रुपये है। डीआरआई ने दो ऐसे व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है जिन्हें रियाद से आए माल को लेना था और उसकी निकासी में सहायता करनी थी।

कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद मौसम में सुधार, श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ानें बहाल

श्रीनगर : कश्मीर घाटी में शुक्रवार को भारी बर्फबारी और बारिश के एक दिन बाद शनिवार को मौसम में सुधार देखने को मिला, जिससे उड़ान सेवाएं बहाल कर दी गईं। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि पूरी घाटी में रात का तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया। अधिकारियों के अनुसार, कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार देर रात तक रुक-रुककर बर्फबारी और बारिश होती रही। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान घाटी के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई। इस मामले में आरोपी मुश्ताक आदम तसिया और मोहम्मद ताहिर हुसैन सहित अन्य लोग तापी, सूत, वलसाड, नवसारी, नर्मदा और गुजरात के अलग जिलों के वन्यजीव अभयारण्यों से वन अधिकारियों की अनुमति के बिना खेर के पेड़ अवैध रूप से काटने में शामिल थे। खेर की लकड़ी काफी टिकाऊ होती है।

जुबिन के परिवार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, गायक की मौत के मामले में त्वरित सुनवाई की मांग की

गुवाहाटी : असम के लोकप्रिय गायक रहे जुबिन गर्ग के परिवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में उनकी मौत के संबंध में त्वरित सुनवाई और द्वितीय देश में उचित राजनयिक-कानूनी कार्रवाई के लिए एक विशेष अदालत गठित करने का अनुरोध किया। परिवार ने यह भी अनुरोध किया कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक मामले के किसी भी आरोपी को जमानत न दी जाए। गर्ग की पत्नी गरिमा, बहन पालमी बोरठाकुर और चाचा मनोज कुमार बोरठाकुर द्वारा हस्ताक्षरित जापन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ईमेल के माध्यम से भेजा गया है। गरिमा ने फेसबुक पर जापन साझा करते हुए लिखा, “हमारे देश के गौरवशाली 7वें गणतंत्र दिवस के उत्सव से पहले, मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी शुभकामनाएं दीं और असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु से संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बारे में अपने परिवार की ओर से एक जापन भी भेजी।”

यमुना में अमोनिया का स्तर घट रहा है, अब दिल्ली में जलापूर्ति में सुधार होगा: दिल्ली सरकार

नयी दिल्ली : यमुना में अमोनिया का स्तर घट रहा है जिससे दिल्ली में जलापूर्ति की स्थिति में सुधार हो सकता है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने यह बात कही। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पांच जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) में पानी में अमोनिया का स्तर इतना अधिक है कि उसका शोशन संभव नहीं है, जिसके कारण दिल्लीवासियों को पानी की आपूर्ति कम हो गई थी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “वज्रीराबाद जलाशय में यमुना नदी के पानी में अमोनिया का स्तर लगभग 2.5 पीपीएम होने के कारण वज्रीराबाद जल शोधन संयंत्र में लगभग 85 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहा है।”

उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश से बढ़ी ठिठुरन, कई सड़कें बंद



देखने को मिला और एक्युआई ‘मध्यम’ श्रेणी में 176 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार को आंशिक बादल और सामान्य से कम तापमान का अनुमान बताया है। कश्मीर में मौसम सुधरने से श्रीनगर

हवाई अड्डे पर उड़ानें फिर शुरू हो गईं, लेकिन घाटी में रात का तापमान शून्य से काफी नीचे बना हुआ है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से 12 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। ‘चिल्ला-ए-कलां’ के दौर में

कांग्रेस से कुछ ’मतभेद’ हैं, इन्हें नेतृत्व के समक्ष उठाऊंगा: शशि थरूर

सोमवार को एक और पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और सड़कें साफ करने का अभियान जारी है। हिमाचल प्रदेश में 680 से अधिक सड़कें बंद रहीं और हजारों घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान शून्य से 7.2 डिग्री नीचे रहा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड जारी है, जहां कई स्थानों पर तापमान शून्य के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है, जबकि दक्षिणी राज्यों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

कांग्रेस से कुछ ’मतभेद’ हैं, इन्हें नेतृत्व के समक्ष उठाऊंगा: शशि थरूर



“दक्किनार” करने की कोशिश की जा रही है। थरूर ने कहा, “मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मुझे सार्वजनिक मंच पर नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेतृत्व के समक्ष उठाना होगा... मैं संसद सत्र के लिए दिल्ली जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मुझे पार्टी नेतृत्व के

गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब में रेलवे की पटरी पर विस्फोट, मालगाड़ी का लोको पायलट घायल

चंडीगढ़ : पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में सरहिंद स्टेशन के पास रेलवे की पटरी के एक हिस्से पर हुए मामूली विस्फोट में मालगाड़ी का लोको पायलट घायल हो गया, जबकि ट्रेन के इंजन को भी क्षति पहुंची है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। रोपड़ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) नानक सिंह ने कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह आतंकी घटना थी या नहीं। ‘प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन’ खलिस्तान जिंदाबाद फोर्स’ से जुड़ा एक अपुष्ट बयान सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर संगठन ने गणतंत्र दिवस से ठीक

विशेष पुनरीक्षण को लेकर कोई विवाद नहीं, हिंदुओं, असमिया मुसलमानों को नोटिस नहीं मिले: हिमंत

गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर कोई विवाद नहीं है और उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के लिए किसी भी हिंदू या असमिया मुस्लिम को किसी प्रकार का नोटिस नहीं भेजा गया है। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य में मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान केवल ‘मिया’ (बांग्ला भाषी मुस्लिम) लोगों को ही नोटिस भेजे जा रहे हैं, ताकि उन्हें दबाव में रखा जा सके। शर्मा ने नलबाड़ी जिले में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा, विशेष पुनरीक्षण को लेकर कोई विवाद नहीं है। किस हिंदू को नोटिस मिला है? किस असमिया मुस्लिम को नोटिस मिला है? मिया और ऐसे लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, वरना वे हमारा फायदा उठाएंगे।

इसरो 2026 में कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा: नारायणन

कोयंबटूर (तमिलनाडु) : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी नारायणन ने शनिवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी 2026 में कई उपग्रह प्रक्षेपणों पर काम कर रही है। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बातचीत में कहा, “हम इस साल कई उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहे हैं। इस दिशा में काफी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) से मुलाकात के बाद हम इनकी घो-षणा करेंगे।” अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कहा था कि भारत और अमेरिका को संयुक्त रूप से अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर काम करना चाहिए। उनकी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर नारायणन ने कहा, “कई बड़े मिशन तैयार हैं। हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) स्थापित करने की



योजना बना रहे हैं। हम इसान को चंद्रमा पर भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की योजना बना रहे हैं।” नारायणन ने कहा कि भारत के लगभग 60 भिन्न देशों के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण में मजबूत सहयोग है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग लाभकारी साबित हुए हैं। पीएसएलवी-सी62 रॉकेट के तीसरे चरण के दौरान सामने आई गड़बड़ी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक इसका विश्लेषण कर रहे हैं।

गुजरात के बनासकांठा में एसयूवी और ट्रक की टक्कर में छह लोगों की मौत, तीन घायल



पालनपुर (गुजरात) : गुजरात के बनासकांठा जिले में एक ट्रक की एक ‘स्पोटर्स यूटिलिटी व्हीकल’ (एसयूवी) से शनिवार को टक्कर होने से एक महिला समेत छह लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना अबू-पालनपुर राजमार्ग पर इकबालगढ़ गांव के निकट शाम लगभग सात बजे हुई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात से राजस्थान की ओर जा रहे एक ट्रक की विपरीत दिशा से आ रही एक एसयूवी से टक्कर हो गई। अमीरगढ़ पुलिस थाने के निरीक्षक पी दी गोहिल ने बताया

कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। गोहिल ने कहा, “राजस्थान के नौ व्यक्ति एक मरीज के इलाज के लिए एसयूवी में पालनपुर जा रहे थे। इकबालगढ़ के निकट, एसयूवी की टक्कर एक ट्रक से हो गई, जो डिवाइडर को पार करके सड़क के दूसरी ओर जा गिरा। इस दुर्घटना में एक महिला समेत छह लोगों की मौत हो गई।” उन्होंने बताया कि एसयूवी में सवार एक महिला और दो पुरुष घायल हो गये और उन्हें निकटवर्ती एक अस्पताल में ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और ट्रक चालक को पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दीमापुर-कोहिमा परियोजना का काम तेजी से चल रहा है, नगालैंड की राजधानी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ेगी

नयी दिल्ली : पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (एनएफआर) ने शुक्रवार को कहा कि 78.42 किलोमीटर लंबी दीमापुर-कोहिमा रेलवे लाइन परियोजना का काम तेजी से चल रहा है तथा नगालैंड की राजधानी कोहिमा को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। एनएफआर के अनुसार, परियोजना का लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष भाग पर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा, “ यह नई लाइन नगालैंड में दीमापुर के पास लुमर्डिंग-तिनसुकिया मुख्य लाइन पर स्थित धनसिरी स्टेशन से शुरू होती है और कोहिमा शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर, बाहरी इलाके में स्थित जुब्जा तक जाती है।” उन्होंने कहा, “यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित की गई। यह नई रेल परियोजना कोहिमा और राष्ट्रीय राजधानी के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगी। इस परियोजना का दिसंबर 2029 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है।” इस परियोजना की प्रगति का उल्लेख करते हुए एनएफआर ने कहा कि मार्ग पर पड़ने वाले आठ स्टेशनों – धनसिरी, धनसिरीपार, शोखुवी, मोल्चो, फेरिमा, पिकेमा, मेंगुजुमा और जुब्जा में से चार का काम पूरा हो चुका है जो धनसिरी, धनसिरीपर, सुखोवी और मोल्चोमा हैं। अधिकारियों ने बताया, “इस मार्ग पर कुल 31,169 मीटर लंबाई की 20 सुरंगें हैं, जिनमें से सात का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 30 बड़े और 150 छोटे पुल हैं। फिलहाल, 12 बड़े पुल और 141 छोटे पुल बनकर तैयार हो गये हैं।”

गणतंत्र दिवस: वर्ष 1965 के युद्ध के नायक की पोती, पूर्व सैनिक का बेटा परेड टुकड़ी के कमांडरों में शामिल

नयी दिल्ली : दूसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट अमित चौधरी गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर स्काउट्स की मिश्रित टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे, लेकिन उनके लिए यह एक व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ-साथ उनके पिता के प्रति एक यादगार श्रद्धांजलि भी होगी, जो वर्ष 1990 के गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा थे। उच्च पर्वतीय इलाकों और खराब मौसम के लिए बने विशेष बूट और विशेष धूप के चरमों के साथ बहुस्तरीय वर्दी पहने चौधरी और उनकी टुकड़ी के सदस्यों ने शुक्रवार को बारिश के बीच परेड के ‘फुल ड्रेस रिवर्सल’ में भाग लिया। ‘अरुणाचल स्काउट्स’ के इस युवा अधिकारी ने, यहां होने वाले इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाग लेने वाली कई अन्य सैन्य टुकड़ियों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ पूर्वाभ्यास के बाद इंडिया गेट के पास एक सैन्य इकाई के परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, “मैंने हमेशा परेड का हिस्सा बनने का सपना देखा है। बचपन में, मैं टीवी पर परेड देखता था और घर के कमरे में मार्च करता था। मेरे पिता वर्ष 1990 में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल थे और वह ‘ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स’ की टुकड़ी का हिस्सा थे।”

केंद्र सरकार ने आईएसएस, आईपीएस, आईएफओएस अधिकारियों के लिए कैडर आवंटन नीति में बदलाव किया

जाता है। इसने कैडर आवंटन के लिए पूर्व की पांच जोन प्रणाली को समाप्त कर दिया है और नए समूह पेश किए हैं जिसमें “सभी राज्य कैडर/संयुक्त कैडरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है और चार समूहों में विभाजित किया गया है।” ग्रुप-एक में एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश), आंध्र प्रदेश, असम-मेघालय, बिहार और छत्तीसगढ़ हैं और ग्रुप-दो में गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश शामिल हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी को जारी नीति के अनुसार, समूह-तीन में महाराष्ट्र, मणिपुर, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु शामिल हैं, जबकि समूह-चार में तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर

केंद्र सरकार ने आईएसएस, आईपीएस, आईएफओएस अधिकारियों के लिए कैडर आवंटन नीति में बदलाव किया

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तीन प्रमुख केंद्रीय सेवाओं के नौकरशाहों के लिए कैडर आवंटन को लेकर एक नयी नीति लागू की है, जिसमें उनकी तैनाती के लिए नए समूह समेत अन्य प्रावधान भी शामिल हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के अधिकारियों के लिए हाल में जारी की गई नीति में कहा गया है कि संबंधित मंत्रालय, किसी वर्ष की एक जनवरी को कैडर अंतराल के अंशों के आधार पर रक्तियों को निर्धारण करेंगे। कैडर या संयुक्त कैडर से तात्पर्य किसी राज्य या राज्यों के समूह या केंद्र शासित प्रदेशों से है जो इन तीनों सेवाओं के अधिकारियों को आवंटित किए जाते हैं, जिन्हें अखिल भारतीय सेवाएं भी कहा

भारत के युवाओं को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए: राजनाथ

नयी दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि ऐसे वक्त जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, तब भारत के युवाओं को मजबूत रहना चाहिए एवं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटों के एक समूह को संबोधित करते हुए, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की “कठोर कार्रवाई” के बारे में भी बात की और उनसे (कैडेटों से) ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। सिंह ने एनसीसी कैडेटों को देश की दूसरी रक्षा पंक्ति बताया। उन्होंने कहा, “भारतीय

सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) में स्थित आतंकी ढांचों को नष्ट कर दिया, जो पहलगाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण और कारगरतापूर्ण आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब था।” रक्षा मंत्री ने कहा, “हमारे सैनिकों ने साहस और संयम से काम

लिया। हमने केवल उन्हीं को निशाना बनाया और नष्ट किया, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, किसी और को नहीं। यह इसलिए संभव हो पाया, क्योंकि वे (हमारे सैनिक) शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हैं।” सिंह ने युवाओं का वर्णन महाभारत के अभिमन्यु के रूप में किया, जो किसी भी प्रकार के ‘चक्रव्यूह’ में प्रवेश करना और उससे विजयी होकर निकलना जानता था। उन्होंने एनसीसी कैडेटों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को साकार करने में योगदान देने का भी आग्रह किया।

भारत ने विदेशों में 70 से अधिक भगोड़ों का लगाया पता, 203 वांछित अपराधी देश में गिरफ्तार

नयी दिल्ली : भारत ने वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न मामलों में वांछित 70 से अधिक भगोड़े अपराधियों का विदेशों में पता लगाने में सफलता हासिल की है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में कुल 71 वांछित या भगोड़े विदेशों में चिन्हित किए गए, जो पिछले एक श्रावक से अधिक समय में सबसे अधिक संख्या है। इसी अवधि में अन्य देशों द्वारा वांछित 203 भगोड़े भारत में पकड़े गए। रिपोर्ट के मुताबिक, बीते वित्तीय वर्ष में 27 भगोड़े या वांछित व्यक्ति विदेश से भारत लौटे। इन मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो इंटरपोल

के लिए भारत की नोडल एजेंसी ‘नेशनल सेंट्रल ब्यूरो’ के रूप में कार्य करती है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच विदेशों में कुल 74 अनुरोध पत्र भेजे गए, जिनमें से 54 सीबीआई से जुड़े मामलों और 20 राज्य पुलिस व अन्य केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित थे। इनमें से 47 अनुरोध पत्रों का पूर्ण निष्पादन किया गया, जबकि 29 मामलों में आंशिक कार्रवाई के बाद पत्र बंद या वापस ले लिए गए। 31 मार्च तक विभिन्न देशों के पास कुल 533 अनुरोध पत्र लंबित थे, जिनमें 276 सीबीआई और 257 राज्य पुलिस तथा अन्य एजेंसियों के थे। वहीं, विदेशी एजेंसियों से 32 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए, जिनमें आपराधिक मामलों की जांच में सहयोग मांगा गया था।

उच्च न्यायालय ‘प्राथमिक प्रहरी’, उन्हें अधिक सक्रिय होना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश

मुंबई : भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि उच्च न्यायालयों को कानून के शासन में व्यवस्थागत विफलताओं को लेकर अधिक सतर्क और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, न्याय में देरी न केवल न्याय से इनकार है, बल्कि न्याय का विनाश है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता और सुलह के तंत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधान न्यायाधीश ने यहां दो कार्यक्रमों में अपने विचार रखे। उन्होंने फली नरीमन स्मृति व्याख्यान में बोलने के बाद बंबई उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित

विफलताओं को लेकर अधिक सतर्क और सक्रिय रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में अपने दरावाजे पर दस्तक दिए जाने का इंतजार न करें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “न्याय की

सुलभता को राज्य की ओर से गारंटीकृत सेवा के स्वनतः प्रदत्त अधिकार (वैसिव राइट) में बदलना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। न्याय में देरी न केवल न्याय से इनकार है,

बल्कि न्याय का विनाश है।” बंबई उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने अदालत कक्ष से परे विवादों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “न्याय का भविष्य न केवल विवादों के कुशल निपटारे पर, बल्कि उन्हें बुद्धिमतापूर्वक सुलझाने पर भी निर्भर करता है। मध्यस्थता और सुलह केवल सुविधा के विकल्प नहीं हैं, बल्कि परिपक्व न्याय के साधन हैं।” प्रधान न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च न्यायालय केवल शीघ्र अदालत तक पहुंचने का माध्यम नहीं हैं।



अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। फली नरीमन स्मृति व्याख्यान में अपने संबोधन में प्रधान न्यायाधीश ने उच्च न्यायालयों से कानून के शासन में व्यवस्थागत

